

कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मसूरी बाईपासरोड़, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून, पुलिस नं०-6 के समीप)

Email:- Stampregndptuk@yahoo.co.in

पत्रांक : 1750 / म०नि०नि० / 2023-24

दिनांक : 19 मार्च, 2024

सेवा में,

1. समस्त अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) /
जिला निबंधक उत्तराखण्ड।
2. समस्त सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड।

विषय:- उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2023 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में
मैन्यूफैक्चरिंग (विनिर्माण क्षेत्र) के अंतर्गत आच्छादित उद्योग स्थापित करने के संबंध
में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना/आदेश संख्या 199665/2024/
XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 16 मार्च 2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके
द्वारा उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2023 के सम्बन्ध में कतिपय निर्णय लिये गये
हैं।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार
कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:-यथोक्त।

Signed by Atul Kumar
Sharma

Date: 19-03-2024 17:19:41

भवदीय

(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबंधन,
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं संख्या उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव (वित्त अनुभाग-9), उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त उपनिबंधक, उत्तराखण्ड।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून: दिनांक: 16 मार्च, 2024

અધિસચના / આદેશ

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 (समय-समय पर यथासंशोधित) सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्यक विचारोंपरान्त लिये गये निर्णय के कम में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैं:-कि.

“उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, 2023” के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में मैन्यूफैक्चरिंग (दिनिमार्ण क्षेत्र) के अन्तर्गत आच्छादित उद्योग स्थापित करने के लिये, ऐसे मामलों में जिनमें उद्यमियों/विधिक व्यक्ति द्वारा एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) पर आवेदन किया गया है, भूमि क्रय किये जाने पर क्षेत्र विशेष की निर्धारित अकृषि दर की 50 प्रतिशत दरें, प्रभावी होंगी;

परन्तु ऐसे विलेशों के माध्यम से अन्तरित भूमि का मूल्यांकन उक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित कृषि दर के अनुसार आंकलित मूल्यांकन से 50 प्रतिशत से न्यून/अधिक नहीं होगा।

अग्रोत्तर यह कि जिन क्षेत्रों में अकृषि भूमि की 50 प्रतिशत दरें, उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि हेतु निर्धारित दरों से न्यून होंगी, तो ऐसे प्रकरणों में कृषि भूमि हेतु निर्धारित सामान्य दर से 50 प्रतिशत अधिक दरें प्रवृत्त होगी, परन्तु किसी भी दशा में अकृषि दरों से अधिक नहीं होगी।”

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 16-03-2024 10:33:33

(दिलीप जातलाकर)

सचिव ।

संख्या:- ११६६५ (१)/XXVII(१)/2024/स्टाम्प-८०/२००९ तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड को मा० मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. निजी सचिव, मा० वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा० वित्त मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ ।
4. सचिव, उद्योग, उत्तराखण्ड शासन ।

